

RCEP को लेकर भारत करेगा पुनर्विचार

प्रलिस के ललल:

वशिव बैंक, कषेतरीय वुयापक आरुथकल ढागीदारी (RCEP), वैशुवलकल डुलुय शंखला (GVC), राषुटरीय लॉजसुटकलस नीतल- 2022, FDI, डुकुत वुयापार सडडुऑते (FTA), राषुटरीय इलेकुकुऑनकलस नीतल-2019, उतुतुडदन आधरतल डुरतुसुआहन (PLI) डुऑनन 2020, आसुडलन (ASEAN)

डेनुस के ललल:

कषेतरीय सडुडु और डररत डर इसकल डुरडवल, RCEP कु लेकर डररत की कलतलरुँ

सुरतु: इकऑनुडकुस टरडुस

कुरकल डें कुरुऑ?

हलल ही डें वशिव बैंक के नवलनतड इंडुडल डेवलडडेंट अडडुडेट: इंडुडलऑ अडरकडुनुतल इन अ केंऑगल गलुडल कऑनुटेकसुट डें, डररत कु कषेतरीय वुयापक आरुथकल ढागीदारी (RCEP) डें शलडलल हुने डर डुनुर्वलकलर कुरने कल सुऑवल दलल गलल ।

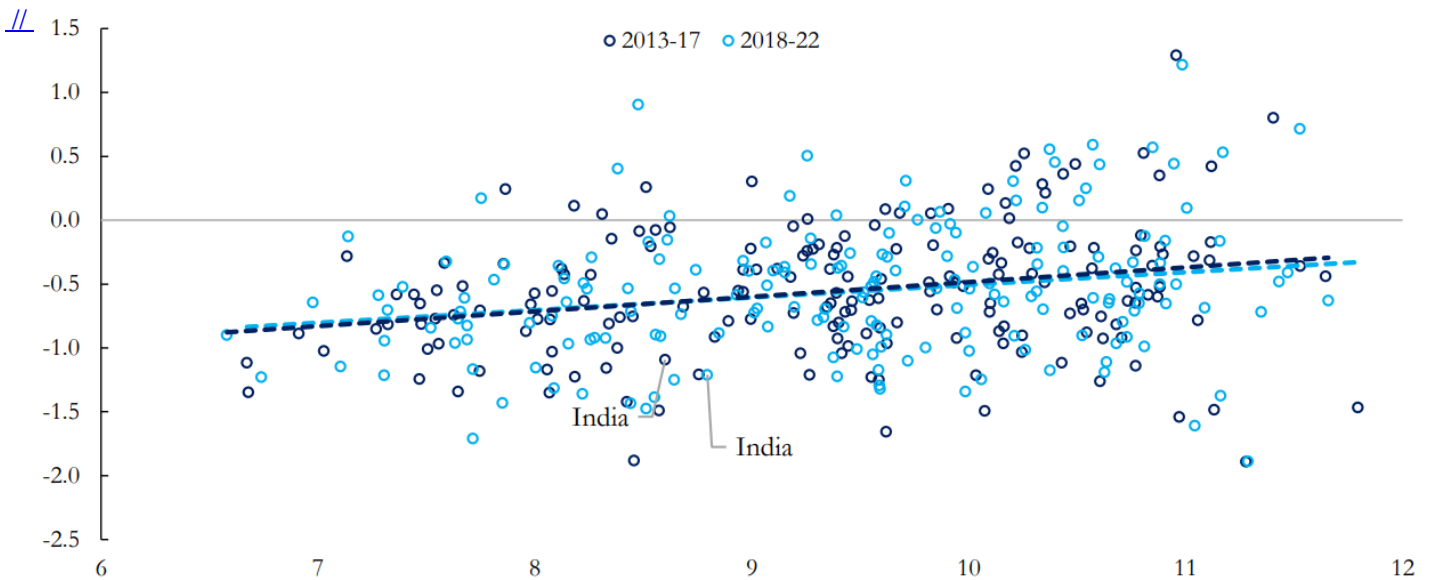
- डक डररतुड थकल टैक ने इस वलकलर कु डर कलहते हुड खरऑऑ कुर दलल कल डर तुरुऑडूरुण डरनुडतलऑ और डुररने अनुडरनुऑ डर आधरतल है ।

डररत के RCEP से हकने के डररे डें वशिव बैंक कल वशलुषण कुरल है?

- आड ललड: वशिव बैंक के एक अधुडडन के अनुसलर डद डररत सडडुऑते डें डरल सेशलडलल हुतल है तु उसकल आड डें सललरन 60 डललडलन अडरलकी डऑलर की वुदुधल हुगल और डद वलह ऐसल नलल कुरतल है तु 6 डललडलन अडरलकी डऑलर की कडु आरुगल ।
 - डे ललड ककुकु डलल, हलकल और उनुनत वनलरुडलण एवं सेवलऑ सललतल वडलनलन कषेतुरुँ डें हुंगे ।
- नरुडत वुदुधल: RCEP डें शलडलल हुने से वडलणन, बैंकल और कंडुडुऑर सललतल सेवलऑ के नरुडत डें संडलवतल 17% की वुदुधल अनुडरन है ।
- आरुथकल ललड से इनकलर: डररत के डलनल RCEP (डररत के डलनल) से वैशुवलकल सकल डररेलु उतुतुड डें 186 डललडलन अडरलकी डऑलर की वुदुधल हुगल और सदसुड देशुँ के सकल डररेलु उतुतुड डें सुथलडु आधर डर सललरन 0.2% की वुदुधल हुगल ।
 - डुखुड ललडररुथी कलन (85 डललडलन अडरलकी डऑलर), ऑलडलन (48 डललडलन अडरलकी डऑलर) और दकषण कुररुडल (23 डललडलन अडरलकी डऑलर) हुंगे ।
 - डररत RCEP से हुने वलले आरुथकल ललड कल एक डऑ हसलसल खु देगल ।
- वुयापार वडलथन/सुथलनलंतरण ऑखडल: RCEP से डलहर रहने से डररत कु वुयापार सुथलनलंतरण कल सलडनल कुरनल डऑ सकतल है, कुरुऑकल वुयापार डलुऑक के सदसुड आडूरुतल शंखललऑ कु सुथलनलंतरतल कुर सकते हुँ और आडस डें डुरतसलडरुदुधल डऑ सकते हुँ, ऑसलसे संडलवतल रूड से RCEP राषुटुरुँ डें डररत दुरलरल नरुडत कु नुकसलन डहुँक सकतल है ।
- संडलवतल नरु सदसुड: डलंगुलदलश और शुरुलंकल ऑसे दकषणल एशुडलरुई देशुँ ने हलल ही डें RCEP डें शलडलल हुने डें रुकलदलखलरुई है ।
 - वलसुतव डें डररत RCEP के डुरडलवुँ से डुरु तरह डुकुत नलल सकतल, कुरुऑकलशुरुलंकल ऑसे देशुँ के सलथ डररत के डुकुत वुयापार सडडुऑते (FTA) है ।

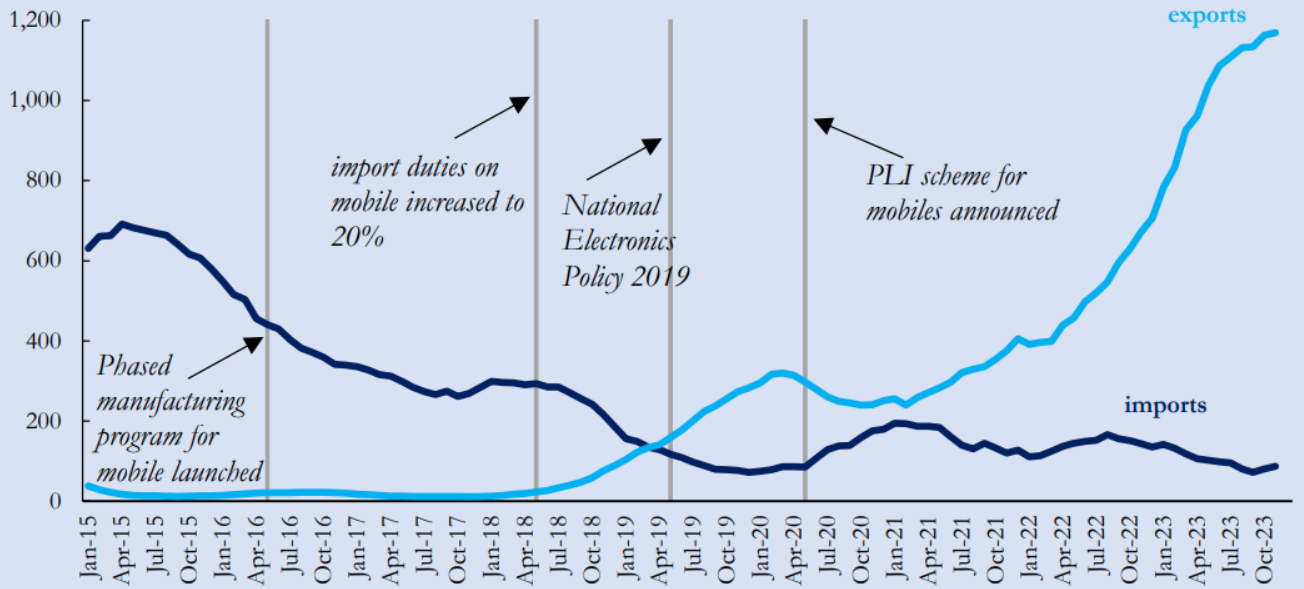
डररत की नरुडत रणनीतल और वुयापार नीतल के संदरुड डें वशिव बैंक कल डुलुडलंकन कुरल है?

- नरुडत वलवलधलकुरण कल आवशुडकतल: सडडु के सलथ सकल डररेलु उतुतुड के डुरतशत के रूड डें डररत कल वसुतु वुयापार कड हुआ है तथल वैशुवलकल डुलुय शंखललऑ (GVC) डें इसकल डलगीदरल डु कड हुई है ।
 - वसुतुर, डररधलन, कडडु और ऑते ऑसे अधकल शुरड-डुरधलन कषेतुरुँ डें वसुतलर कुरके वलवलधलकुरण हलसलल कलल ऑल सकतल है ।
 - डररधलन, कडडु, वसुतुर और ऑते (Apparel, Leather, Textiles, and Footwear- ALTF) के वैशुवलकल नरुडत डें डररत की हसलसेदरल वरुष 2002 के 0.9% से डदकुर वरुष 2013 डें 4.5% के शखलर डर डहुँक गरुई, लेकनल वरुष 2022 डें डर हसलसेदरल डककुर 3.5% रह गरुई ।



- **GVC की भागीदारी में वृद्धि:** GVC में एकीकरण करके भारत:
 - उच्चतर मूल्यवर्धित वस्तुओं के उत्पादन में भाग लेकर अपने **उत्पादन की विविधता** का विस्तार करेगा।
 - उन्नत प्रौद्योगिकियों और वैश्विक बाजारों तक पहुँच प्राप्त करके अपनी **प्रतस्पर्द्धात्मकता** को बढ़ाएगा।
 - भारत में उत्पादन करने की इच्छुक बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा **FDI** प्रवाह में वृद्धि करेगा।
- **उदारीकरण और संरक्षणवाद में संतुलन:** भारत की व्यापार नीति में **उदारीकरण और संरक्षणवाद** दोनों ही उपाय शामिल हैं। उदाहरण के लिये, **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022** और **डिजिटल सुधार** जैसी पहलों का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना तथा व्यापार सुगमता में सुधार करना है।
 - इसके विपरीत संरक्षणवादी उपायों में पुनः वृद्धि हुई है, जैसे **टैरिफ में वृद्धि और गैर-टैरिफ बाधाएँ**, जो भारत के खुले व्यापार को प्रतर्बिधति करती हैं।
- **व्यापार समझौते:** हाल ही में UAE और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ हुए **मुक्त व्यापार समझौते (FTA)** अधिमान्य व्यापार समझौतों की ओर बदलाव का संकेत देते हैं। हालाँकि भारत संभावित लाभों के बावजूद **क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP)** जैसे बड़े व्यापार ब्लॉकों में शामिल होने से बचना रहा है।
- **भारत की टैरिफ और औद्योगिक नीतियों का पुनर्मूल्यांकन:** भारत मोबाइल फोन का शुद्ध निर्यातक बन गया है क्योंकि **राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019**, **उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना 2020** जैसी नीतियों के कारण आयात में गैरिफ्ट के बीच निर्यात में वृद्धि हुई है।
 - हालाँकि **प्रमुख मध्यवर्ती सुझावों पर आयात शुल्क में हाल ही में की गई वृद्धि**, जिसने वर्ष 2018 और 2021 के बीच औसत शुल्क को 4% से 18% तक ला दिया है, इस क्षेत्र की **प्रतस्पर्द्धात्मकता को खतरे में डालती है**।
- **भारत के लिये अवसर:** भू-राजनीतिक जोखिमों की बढ़ती धारणा ने कंपनियों को अपनी **सोर्सिंग रणनीतियों में विविधता लाने हेतु** प्रेरित किया है।
 - यह भारत जैसे देशों के लिये एक अवसर प्रस्तुत करता है, जहाँ **प्रचुर कार्यबल और बढ़ता हुआ वनिरिमाण आधार** है।

(USD mm, 12 months rolling average)



भारत RCEP में शामिल होने पर पुनर्विचार क्यों अनिश्चित रहा है?

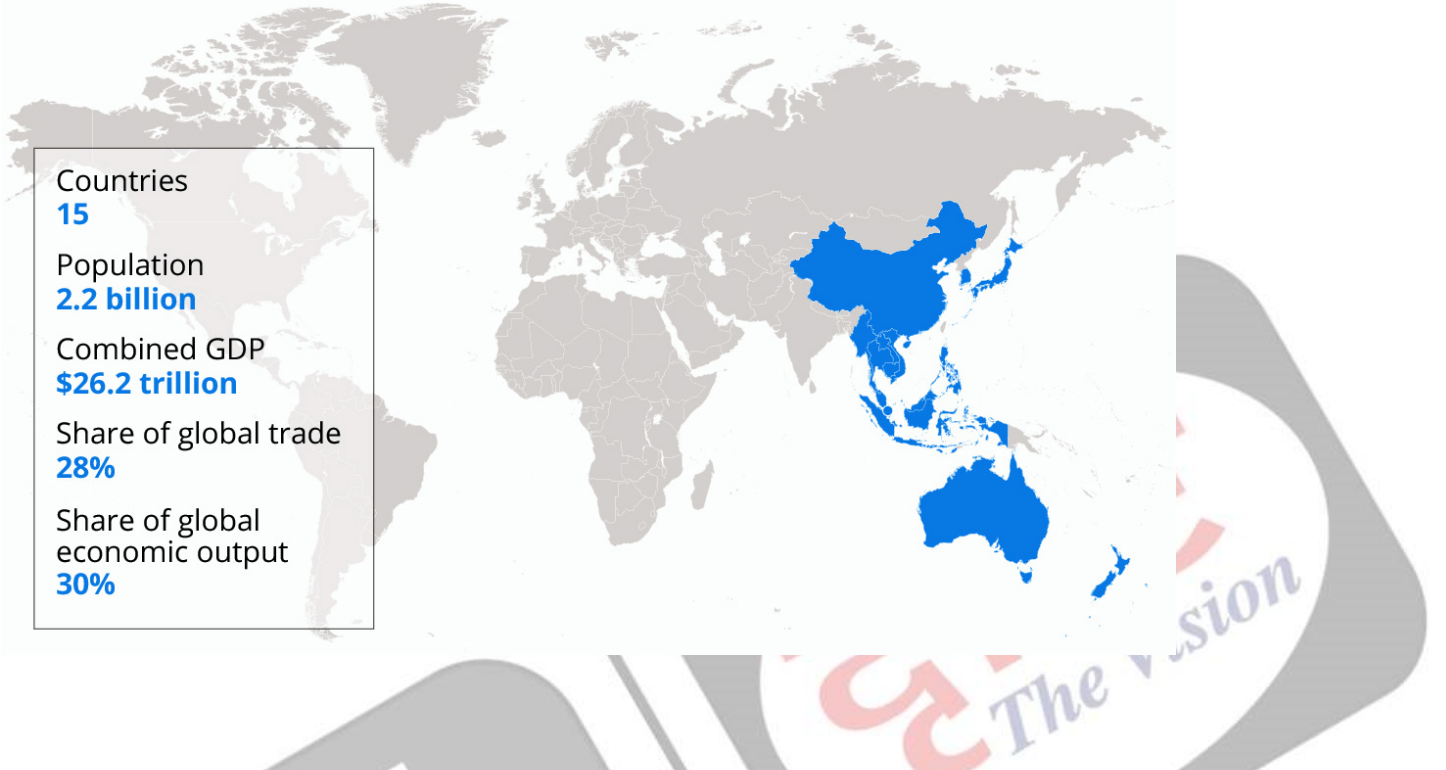
- **वशिव बैंक के सुझाव में त्रुटिपूर्ण धारणाएँ:** वशिव बैंक के अध्ययन में वर्ष 2030 तक 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आय वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, लेकिन इसमें यह नहीं माना गया है कि इनमें से अधिकांश लाभ आयात में वृद्धि से आएगा, जिससे व्यापार असंतुलन उत्पन्न होगा।
- **RCEP सदस्यों के बीच व्यापार घाटा:** RCEP के चालू होने के बाद से चीन के साथ **आसियान** का व्यापार घाटा वर्ष 2020 में 81.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2023 में 135.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।
 - इसी तरह चीन के साथ **जापान** का व्यापार घाटा वर्ष 2020 में 22.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2023 में 41.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था।
 - दक्षिण कोरिया को वर्ष 2024 में पहली बार चीन के साथ व्यापार घाटे का भी सामना करना पड़ सकता है।
- **चीन-केंद्रित आपूर्ति शृंखलाओं पर अत्यधिक निर्भरता:** RCEP सदस्यों का बढ़ता व्यापार घाटा **चीन-केंद्रित आपूर्ति शृंखलाओं** पर बढ़ती निर्भरता को उजागर करता है।
 - यह निर्भरता महत्वपूर्ण जोखिम प्रस्तुत करती है, विशेष रूप से वैश्विक आपूर्ति शृंखला व्यवधानों के संदर्भ में, जैसा **कक्रोवडि-19 महामारी** के दौरान अनुभव किया गया।
- **अनुचित परतसिपर्द्धा:** RCEP में शामिल न होकर भारत ने अन्य व्यापार समझौतों की संभावनाओं को तलाशना जारी रखा, जो चीन के पक्ष में अनुचित रूप से न हों या उसके आर्थिक हितों के लिये खतरा न हों।
 - चीन के साथ भारत का **व्यापार घाटा वर्ष 2023-24 में बढ़कर 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर** होगा।
- **वैकल्पिक व्यापार समझौते:** भारत के पास पहले से ही न्यूज़ीलैंड और चीन को छोड़कर 15 RCEP सदस्यों में से 13 के साथ कई कार्यात्मक **मुक्त व्यापार समझौते (FTA)** हैं।
- **"चाइना+1" रणनीति:** RCEP में शामिल न होने का भारत का नरिणय, चीन पर निर्भरता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिये **"चाइना+1"** रणनीति अपनाने की वैश्विक प्रवृत्ति के अनुरूप है।

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) क्या है?

- RCEP 10 आसियान देशों और उनके पाँच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) भागीदारों: **चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड** के बीच एक व्यापार समझौता है।
- RCEP को नवंबर 2011 में **19वें आसियान शिखर सम्मेलन** के दौरान प्रस्तुत किया गया था और नवंबर 2012 में इस पर चर्चा शुरू हुई थी।
 - RCEP 1 जनवरी, 2022 को लागू हुआ।
- संयुक्त GDP (**26 ट्रिलियन डॉलर**), जनसंख्या (**2.27 बिलियन**) और हस्ताक्षरकर्ता पक्षों के कुल नरियात मूल्य (**5.2 ट्रिलियन डॉलर**) के अनुसार यह वशिव का सबसे बड़ा FTA है।

15 Countries Sign World's Biggest Free Trade Deal

Key facts about the Regional Comprehensive Economic Partnership free trade deal



आगे की राह

- **द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते (FTA):** यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ जैसे नए साझेदारों के साथ व्यापक FTA के लिये बातचीत जल्द से जल्द पूरी की जानी चाहिए।
- **खाड़ी देशों और अफ्रीका के साथ व्यापार समझौते:** भारत को ऊर्जा, बुनियादी ढाँचे और डिजिटल सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए **खाड़ी सहयोग परिषद (GCC)** देशों तथा अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार समझौतों पर सक्रिय रूप से बातचीत एवं विस्तार करना चाहिए।
- **वर्तमान क्षेत्रीय समूहों को सुदृढ़ करना:** भारत को सार्क के भीतर क्षेत्रीय व्यापार एकीकरण की वार्ता जारी रखनी चाहिये और **बमिस्टेक** को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ता है।
- **भारत-प्रशांत आर्थिक रूपरेखा (IPEF):** भारत को चार प्रमुख क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिये **आईपीईएफ** में सक्रिय रूप से भाग लेकर अपनी "एक्ट ईस्ट नीति" को पूरक बनाना चाहिये: व्यापार, आपूर्ति शृंखला लचीलापन, स्वच्छ ऊर्जा और नक्षिपक्ष अर्थव्यवस्था।
- **आत्मनिर्भर भारत:** सरकार को घरेलू वनिरिमाण को बढ़ावा देकर घरेलू वनिरिमाण क्षमताओं और नरियात को बढ़ाना चाहिए। **मेक इन इंडिया 2.0** तथा उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (**PLI**) जैसी योजनाओं को नए सरि से बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

दृष्टिभेन्स प्रश्न:

प्रश्न. क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) से बाहर निकलने के भारत के फैसले का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रलमिस

नमिनलखिति देशों पर वचिर कीजिये: (2018)

- 1- ऑस्ट्रेलिया
- 2- कनाडा

- 3- चीन
- 4- भारत
- 5- जापान
- 6- यू.एस.ए.

उपर्युक्त में से कौन-से देश "आसियान के मुक्त व्यापार साझेदारों" में से हैं?

- (a) 1, 2, 4 और 5
- (b) 3, 4, 5 और 6
- (c) 1, 3, 4 और 5
- (d) 2, 3, 4 और 6

उत्तर: (C)

प्रश्न. 'क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी' शब्द अक्सर समाचारों में देशों के एक समूह के मामलों के संदर्भ में प्रकट होता है: (वर्ष 2016)

- (A) जी20
- (B) आसियान
- (C) एससीओ
- (D) सार्क

उत्तर: (B)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/india-s-hesitancy-in-joining-rcep>

